बुधवार, 10 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा शतक

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

बटवारा 1947 का फर्स्ट लुक जारी

Page-05

**संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर हुई बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी कूटनीतिक बहस देखने को मिली।भारत ने पाकिस्तान पर झूठी सूचनाएं फैलाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उसके दावों को खारिज कर दिया।भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।**

# भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल दुष्प्रचार पर दिया सख्त जवाब

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक टकराव देखने को मिला। बैठक में पाकिस्तान द्वारा उठाए गए मुद्दों और लगाए गए आरोपों का भारत ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करने और झूठी सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया।भारत ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान लगातार धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने की कोशिश करता है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान का रवैया तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए गलत सूचनाओं का सहारा ले रहा है। उन्होंने इसे "धार्मिक शब्दावली में लिपटा आधिकारिक रूप से प्रायोजित दुष्प्रचार अभियान" बताया।भारत ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।

भारत ने यह भी दोहराया कि किसी भी देश को आतंकवादी संगठनों को संरक्षण नहीं देना चाहिए और न ही उन्हें अपनी धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए करने देना चाहिए।बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान के उस रिकॉर्ड की ओर भी संकेत किया, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं को वहां शरण मिलने के आरोप लगते रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि ऐसे देश को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए।भारत की इस प्रतिक्रिया को कई देशों ने गंभीरता से लिया। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूती से रखते हुए पाकिस्तान के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब दिया है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने हितों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

## सहमति से बने रिश्ते को चरित्र का पैमाना नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो बालिग व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को किसी व्यक्ति के चरित्र का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आधुनिक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिएयह फैसला एक सरकारी भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया। मामले में उम्मीदवार के निजी जीवन और उसके पूर्व संबंधों को लेकर प्रश्न उठाए गए थे। अदालत ने कहा कि केवल इसलिए किसी व्यक्ति को अनैतिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका कोई संबंध विवाह तक नहीं पहुंचा।सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि समाज में समय के साथ बदलाव आया है और लोगों की व्यक्तिगत पसंद तथा जीवनशैली को लेकर दृष्टिकोण भी विकसित हुआ है। ऐसे में पुराने सामाजिक मानकों के आधार पर किसी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन करना उचित नहीं है।अदालत ने यह भी कहा कि दो वयस्क व्यक्तियों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध कानून की दृष्टि में अपराध नहीं हैं। इसलिए ऐसे संबंधों को सरकारी नौकरी या अन्य अवसरों में व्यक्ति के खिलाफ आधार नहीं बनाया जा सकता।कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका मानना है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।सामाजिक दृष्टि से भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से भारतीय समाज में विवाह पूर्व संबंधों को लेकर विभिन्न मत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संबंध का समाप्त हो जाना अपने आप में धोखे या अनैतिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च अदालत ने व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश दिया है। साथ ही यह भी रेखांकित किया है कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए।

## TMC विवाद के बीच महुआ मोइत्रा ने साधा निशाना

तृणमूल कांग्रेस में कथित असंतोष और बगावत की खबरों के बीच पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ही दल के कुछ नेताओं पर तीखा हमला बोला है। विशेष रूप से उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि टीएमसी के कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। इन्हीं खबरों के बीच महुआ मोइत्रा ने बिना किसी लाग-लपेट के अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे हैं, उन्हें राजनीतिक नैतिकता का पालन करना चाहिए।महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखी अपनी टिप्पणी में बागी नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने संकेत दिया कि यदि किसी नेता को पार्टी से असहमति है तो उसे स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति बतानी चाहिए। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे नेताओं पर अवसरवाद का आरोप भी लगाया।यूसुफ पठान का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गईं। हालांकि उनकी ओर से तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई। इस बीच टीएमसी समर्थकों और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई।महुआ मोइत्रा अपनी बेबाक शैली के लिए जानी जाती हैं और इससे पहले भी कई राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख चुकी हैं। पार्टी के भीतर चल रहे विवाद पर उनका यह रुख दर्शाता है कि टीएमसी नेतृत्व कथित बगावत की खबरों को गंभीरता से ले रहा है।

## कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में प्रसिद्ध शिक्षक एवं यूट्यूबर खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी के खतरे से राहत मिल गई है।यह मामला उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई एक घटना से जुड़ा है, जिसमें तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग के आरोप लगाए गए थे। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामले में कई लोगों के नाम सामने आए। इसी क्रम में खान सर का नाम भी चर्चा में आया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।सुनवाई के दौरान खान सर के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल का घटना से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और उन्हें अनावश्यक रूप से मामले में घसीटा जा रहा है। बचाव पक्ष ने कहा कि खान सर एक शिक्षक हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, इसलिए गिरफ्तारी से उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है।दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जांच को प्रभावित होने की आशंका जताई। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया।इस फैसले के बाद खान सर के समर्थकों ने राहत व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर भी उनके पक्ष में बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतिम फैसला नहीं है और मामले की अगली सुनवाई में अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे का निर्णय लेगी।फिलहाल अदालत के आदेश से खान सर को अस्थायी राहत मिल गई है, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और मामले का अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

## ग्रेट निकोबार में बनेगा ₹13,000 करोड़ का एयरपोर्ट

भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर लगभग 13,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नया ग्रीनफील्ड सिविल-मिलिट्री एयरपोर्ट विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह परियोजना देश की समुद्री और सुरक्षा रणनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित एयरपोर्ट गलाथिया बे के निकट चिंगेन क्षेत्र में बनाया जाएगा। यह दोहरे उपयोग वाली सुविधा होगी, जिसका इस्तेमाल नागरिक उड्डयन और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इससे क्षेत्र में हवाई संपर्क बेहतर होने के साथ-साथ रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी।यह परियोजना उस व्यापक ग्रेट निकोबार विकास योजना का हिस्सा है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 81,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस योजना में बंदरगाह, ऊर्जा, परिवहन और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास भी शामिल है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह एयरपोर्ट भारत को मलक्का जलडमरूमध्य के निकट रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। मलक्का जलडमरूमध्य विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचा भारत की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा।हालांकि परियोजना को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी सामने आई हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्रेट निकोबार जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। सरकार का कहना है कि सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जाएगा।

## देश में तेजी से आगे बढ़ा मॉनसून, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने इस वर्ष अपेक्षा से तेज गति पकड़ ली है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून की प्रगति सामान्य से बेहतर रही है। इसके प्रभाव से दक्षिण और पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। किसानों के लिए यह स्थिति लाभकारी मानी जा रही है क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई का समय निकट है।महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी व्यक्त की गई है।वहीं,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, यहां गर्मी से तत्काल राहत मिलने की संभावना कम है, हालांकि बादलों की आवाजाही और हल्की हवाओं के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है।विशेषज्ञों का कहना है कि मॉनसून की यह तेज प्रगति कृषि और जल संसाधनों के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियों पर भी नजर रखना आवश्यक होगा।मौसम विभाग लगातार परिस्थितियों की निगरानी कर रहा है और लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। मॉनसून की सक्रियता आने वाले दिनों में देश के और अधिक हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत का दायरा और बढ़ सकता है।

# रूस-यूक्रेन युद्ध में नया मोड़

# पूर्वी मोर्चे पर भीषण संघर्ष से बढ़ी वैश्विक चिंता

**युद्ध का असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, जबकि कई विकासशील देशों को खाद्यान्न आयात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।**

**टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय**

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश करने के बावजूद समाप्ति के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों में पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में संघर्ष तेज हो गया है, जिससे एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। दोनों देशों की सेनाएं रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए लगातार सैन्य अभियान चला रही हैं और युद्ध का दायरा कई महत्वपूर्ण इलाकों तक फैल गया है।यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने पूर्वी मोर्चे पर रूसी हमलों को कई स्थानों पर विफल कर दिया है और कुछ क्षेत्रों में जवाबी कार्रवाई भी की है। वहीं रूस ने कहा है कि उसकी सेना निर्धारित सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि करना कठिन बना हुआ है, लेकिन युद्ध क्षेत्र से आ रही रिपोर्टें लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों की ओर संकेत कर रही हैं।युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ रहा है। हजारों परिवार अब भी विस्थापन का सामना कर रहे हैं और कई शहरों में बिजली, पानी तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन लगातार जारी लड़ाई के कारण सहायता कार्यों में बाधाएं आ रही हैं।इस बीच यूरोपीय देशों और अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य एवं आर्थिक सहायता जारी रखने का संकेत दिया है। पश्चिमी देशों का कहना है कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर रूस ने पश्चिमी देशों पर संघर्ष को लंबा खींचने का आरोप लगाया है और कहा है कि बाहरी हस्तक्षेप से शांति प्रयास प्रभावित हो रहे हैं।युद्ध का असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, जबकि कई विकासशील देशों को खाद्यान्न आयात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में किसी त्वरित समाधान की संभावना कम दिखाई देती है। हालांकि विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन दोनों पक्षों के रुख में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। ऐसे में दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं, जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता रह सकता है।

## कई देशों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ा

**टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय**

एशिया के विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय होने के साथ ही कई देशों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और म्यांमार सहित कई देशों ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है।मौसम विभागों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न होने लगी है। कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून एशियाई देशों की कृषि व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। करोड़ों किसानों की आजीविका वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छी बारिश से फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन अत्यधिक वर्षा से नुकसान की आशंका भी बनी रहती है।थाईलैंड और इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों में पहले ही भारी बारिश के कारण सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन लोगों को नदी किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं।जलवायु विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक मौसम चक्र के कारण चरम मौसमी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एशियाई देशों को आपदा प्रबंधन और जल संसाधन नियोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर सभी देशों की नजर बनी रहेगी।

## देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की तैयारी

## घर-घर पहुंचेंगे 30 लाख गणनाकर्मी

**टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय**

भारत सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारियों को तेज कर दिया है। इस बार देश की जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न कराई जाएगी, जो भारतीय प्रशासनिक इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल कवायद मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही इस योजना को मंजूरी दे चुका है और इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगभग 30 लाख गणनाकर्मी और पर्यवेक्षक इस अभियान में भाग लेंगे।सरकार के अनुसार जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों और परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या से जुड़ा विस्तृत डेटा संकलित किया जाएगा। पहली बार नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल एप और केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली के उपयोग से आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा डेटा संकलन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनेगी। इससे

सरकार को विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधी नीतियों के निर्माण में मदद मिलेगी।विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में डिजिटल जनगणना प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। इससे आंकड़ों के विश्लेषण और सार्वजनिक उपयोग में भी आसानी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि जनगणना के आंकड़े पहले की तुलना में अधिक तेजी से उपलब्ध कराए जाएं ताकि नीति निर्माण में उनका प्रभावी उपयोग हो सके।

## चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ी समुद्री प्रतिस्पर्धा

**टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय**

दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों ने एक-दूसरे पर अपने समुद्री अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए हैं। इस घटनाक्रम ने पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।फिलीपींस का कहना है कि उसके तटरक्षक जहाजों और मछुआरों को विवादित क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर चीन का दावा है कि संबंधित क्षेत्र उसके ऐतिहासिक अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हैं और उसकी गतिविधियां पूरी तरह वैध हैं।दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय बन जाता है।अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से निकालने का आग्रह किया गया है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन दोनों देशों के रुख में अभी कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही है।

# प्रशासन और प्रदर्शनकारी आमने-सामने

## लॉस एंजिलिस में आव्रजन नीति के खिलाफ प्रदर्शन तेज

**टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय**

अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर में आव्रजन नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नई नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हाल में लागू की गई कुछ व्यवस्थाएं प्रवासी समुदायों के हितों के खिलाफ हैं और उनसे लाखों लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।शहर के कई प्रमुख इलाकों में रैलियां और मार्च निकाले गए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली, जिसके बाद प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। अधिकारियों ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है।प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि अमेरिका लंबे समय से विभिन्न देशों से आए प्रवासियों का देश रहा है और नई नीतियां उस परंपरा के विपरीत हैं। कई सामाजिक संगठनों

और मानवाधिकार समूहों ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।वहीं अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि सीमा सुरक्षा और आव्रजन व्यवस्था को प्रभावी बनाना राष्ट्रीय हित में है। अधिकारियों के अनुसार नई नीतियों का उद्देश्य अवैध आव्रजन को नियंत्रित करना और कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना है।राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आव्रजन का मुद्दा अमेरिका में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है और आगामी राजनीतिक माहौल में इसकी अहम भूमिका रहने वाली है। लॉस एंजिलिस में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने इस बहस को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।

## संपादक की कलम से

**पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया है। हाल के दिनों में क्षेत्र में बढ़े सैन्य तनाव, कूटनीतिक गतिरोध और सुरक्षा संबंधी घटनाओं ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यह संकट केवल क्षेत्रीय देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव ऊर्जा बाजार, वैश्विक व्यापार, निवेश और आम नागरिकों के जीवन पर भी पड़ रहा है।दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी तक महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। ऐसे समय में पश्चिम एशिया में अस्थिरता ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों, विशेषकर भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है। तेल महंगा होने का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन, उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है।**

**परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है।भारत के लिए यह स्थिति विशेष महत्व रखती है। देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। पश्चिम एशिया भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार भी है। ऐसे में क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हितों और विदेश नीति पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार संवाद, शांति और कूटनीतिक समाधान की वकालत करता रहा है।हालांकि संकट केवल आर्थिक नहीं है। यदि क्षेत्रीय संघर्ष व्यापक रूप लेता है तो इसका मानवीय प्रभाव भी गंभीर हो सकता है। लाखों लोगों के विस्थापन, मानवीय संकट और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि युद्ध और संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है।आज आवश्यकता इस बात की है कि संबंधित देश संयम का परिचय दें और विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से खोजें। संयुक्त राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है।पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट यह याद दिलाता है कि आधुनिक विश्व में कोई भी क्षेत्रीय संघर्ष वास्तव में केवल क्षेत्रीय नहीं रह जाता। उसका प्रभाव सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसलिए समय की मांग है कि टकराव नहीं, संवाद को प्राथमिकता दी जाए। यही विश्व शांति, आर्थिक स्थिरता और मानवता के हित में सबसे उपयुक्त मार्ग है।**

# तृणमूल कांग्रेस में बढ़ी अंदरूनी कलह कई नेताओं की नाराजगी से ममता सरकार पर दबाव

सूत्रों के अनुसार चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न जिलों से रिपोर्ट मांगी थी। इन रिपोर्टों में कई स्थानों पर संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और स्थानीय स्तर पर समन्वय की कमी जैसे मुद्दे सामने आए हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर नए नेतृत्व को अवसर देना चाहिए

**टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय**

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सामने अब संगठनात्मक एकता बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि और कई वरिष्ठ नेताओं की खुली नाराजगी ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि पार्टी के कुछ सांसद और विधायक नेतृत्व की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं और भविष्य की रणनीति को लेकर अलग-अलग राय रख रहे हैं।सूत्रों के अनुसार चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न जिलों से रिपोर्ट मांगी थी। इन रिपोर्टों में कई स्थानों पर संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और स्थानीय स्तर पर समन्वय की कमी जैसे मुद्दे सामने आए हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर नए नेतृत्व को अवसर देना चाहिए, जबकि एक वर्ग नेतृत्व में व्यापक बदलाव की मांग कर रहा है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि विपक्ष और राजनीतिक विरोधी दल पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता ने स्पष्ट किया कि संगठन को पुनर्गठित किया जाएगा और जनता के बीच जाकर पार्टी की नई रणनीति तैयार की जाएगी।दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी में चल रहे असंतोष को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के कई नेता अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि टीएमसी ने ऐसे दावों को खारिज करते हुए इसे विपक्ष की राजनीतिक अफवाह बताया है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी दल के लिए चुनावी हार के बाद संगठन को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी लंबे समय तक सत्ता में रही और अब विपक्ष की भूमिका में आने के बाद उसे नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। पार्टी के सामने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने, जनाधार को सुरक्षित रखने और नेतृत्व पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की चुनौती है।आने वाले महीनों में यदि पार्टी नेतृत्व असंतुष्ट नेताओं को साथ रखने में सफल रहता है तो टीएमसी पुनर्गठन के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन यदि असंतोष और बढ़ता है तो बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें ममता बनर्जी की अगली राजनीतिक रणनीति पर टिकी हैं।

# बिहार में मंत्री नियुक्ति को लेकर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट में याचिका से राजनीतिक बहस तेज

**टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय**

बिहार की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक बहस तेज हो गई है। राज्य सरकार में हाल ही में किए गए मंत्री पद के एक महत्वपूर्ण नियुक्ति निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने संवैधानिक परंपराओं और राजनीतिक नैतिकता की अनदेखी करते हुए निर्णय लिया है। विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है और विधानसभा से लेकर सार्वजनिक मंचों तक मुद्दा उठाया जा रहा है।वहीं राज्य सरकार ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि नियुक्ति पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप की गई है। सरकार का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने विश्वास जताया है कि न्यायालय में सरकार का पक्ष मजबूत रहेगा।राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मामला केवल एक नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे शासन व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। कई कानूनी विशेषज्ञ भी इस मामले को महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि अदालत का निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मिसाल बन सकता है।फिलहाल सभी पक्षों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत का फैसला न केवल बिहार की राजनीति बल्कि संवैधानिक व्याख्या के स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

# सहयोगी दलों ने कांग्रेस से मांगी बड़ी भूमिका विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा

**टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय**

देश की विपक्षी राजनीति में इन दिनों नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हाल के चुनावी परिणामों के बाद कई क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से गठबंधन के भीतर अपनी भूमिका और भागीदारी को लेकर स्पष्टता की मांग की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्षी दल अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं।सूत्रों के अनुसार कई क्षेत्रीय दलों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता तभी प्रभावी हो सकती है जब सभी सहयोगी दलों को निर्णय प्रक्रिया में बराबर महत्व मिले। कुछ नेताओं ने सीट बंटवारे, साझा कार्यक्रम और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की आवश्यकता जताई है।कांग्रेस नेतृत्व ने सहयोगी दलों की चिंताओं को गंभीरता से लेने का संकेत दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्षी एकता समय की मांग है और सभी दलों के सुझावों का सम्मान किया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए व्यापक सहयोग आवश्यक है।दूसरी ओर भाजपा ने विपक्षी दलों के बीच मतभेदों को उजागर करते हुए कहा है कि गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि विपक्षी दल केवल चुनावी मजबूरी में साथ दिखाई देते हैं और उनके बीच वैचारिक एकरूपता का अभाव है।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में विपक्षी दलों के बीच बैठकों और बातचीत का दौर और तेज होगा। यदि सहयोगी दलों की मांगों का समाधान निकाला जाता है तो विपक्ष एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ सकता है। वहीं मतभेद बढ़ने की स्थिति में कई राज्यों में नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं। फिलहाल विपक्षी राजनीति का केंद्र बिंदु संगठनात्मक समन्वय और नेतृत्व का सवाल बना हुआ है।

# NSUI ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर जताई चिंता

## 'छात्रों को भुगतने के लिए मजबूर नहीं कर सकते'

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर उठे विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। सोमवार को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की वेकेशन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीएसई की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और तकनीकी खामियां हैं, जिससे छात्रों के मूल्यांकन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह याचिका एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की ओर से 29 मई को दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई को ओएसएम प्रणाली को लेकर बार-बार सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करने पड़े हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर संदेह पैदा हुआ है। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि जिन छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी या मूल्यांकन प्रक्रिया पर आपत्ति है, उन्हें मैन्युअल री-चेकिंग और उत्तर पुस्तिकाओं के भौतिक सत्यापन का मौका दिया जाए। दूसरी ओर, सुनवाई के दौरान सीबीएसई के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि याचिका एक राजनीतिक संगठन के छात्र विंग द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हालांकि, एनएसयूआई की ओर से पेश वकील ने जवाब देते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव होने का मतलब यह नहीं है कि संगठन छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। याचिका में कहा गया है कि यदि मूल्यांकन प्रणाली में कोई तकनीकी खामी या कमी है तो उसका नुकसान छात्रों को नहीं उठाने दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्रशासन द्वारा लागू की गई प्रणाली की खामियों की वजह से छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं किया जा सकता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने हाल के वर्षों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को अधिक तेज और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू की है। इस प्रक्रिया में उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परीक्षकों द्वारा जांचा जाता है और वहीं अंक दिया जाता है। हालांकि, अब इस प्रणाली की सटीकता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर इस याचिका के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों की नजरें अब 12 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस मामले में आगे की दिशा तय कर सकती है।

## ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की रेस अब आखिरी दौर में

अगर आपने भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, तो आपके लिए बड़ी खबर है। इस बार शिक्षा विभाग ने आवेदन की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब है कि फॉर्म भरने का काम पूरा हो चुका है और अब छात्र-छात्राओं को बेसब्री से मेरिट लिस्ट का इंतजार है। शेड्यूल के मुताबिक कल यानी 9 जून को कॉलेजों की तरफ से अंतिम वरीयता सूची (फाइनल मेरिट लिस्ट) और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स का नाम इस मेरिट सूची में आएगा, उन्हें 13 जून तक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच करानी होगी और ई-मित्र पर जाकर फीस जमा करनी होगी। इसके बाद 15 जून को कॉलेज पहली प्रवेश सूची जारी करेंगे। वहीं 16 जून को स्टूडेंट्स को उनके सेक्शन और सब्जेक्ट अलॉट कर दिए जाएंगे। इस साल राजकीय कन्या महाविद्यालय (जीडी कॉलेज) में एडमिशन के लिए छात्राओं में जबरदस्त होड़ देखने को मिल रही है। कॉलेज में कुल 2040 सीटें हैं, लेकिन इनके मुकाबले 3849 फॉर्म जमा हुए हैं, यानी सीटों से लगभग दोगुने आवेदन आए हैं। सबसे तगड़ी फाइट बीए और बीएससी में है। जीडी कॉलेज में बीएससी बायो की 176 सीटों के लिए 733 और बीएससी मैथ्स की 264 सीटों के लिए 490 छात्राओं ने दावेदारी ठोकी है। वहीं बीए की बात करें तो यहाँ रिकॉर्ड 2443 आवेदन आए हैं। इसके उलट कॉमर्स (बीकॉम) में इस बार छात्राओं की रुचि बहुत कम दिखी है। जीडी कॉलेज में बीकॉम की 500 सीटें हैं, लेकिन फॉर्म सिर्फ 183 ही आए हैं। ऐसे में यहाँ आधे से ज्यादा सीटें खाली रहने की पूरी संभावना है। सिर्फ जीडी कॉलेज ही नहीं, बल्कि शहर के दूसरे बड़े कॉलेजों में भी आर्ट्स और साइंस संकाय ही स्टूडेंट्स की पहली पसंद बने हुए हैं।

## 25 गेंदों में ठोक दिया अर्धशतक 3 ओवर में 3 विकेट झटके

## तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रज्ञानानंदा को सम्मानित किया

भारतीय शतरंज के लिए यह समय बेहद गौरवपूर्ण माना जा रहा है। युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे में आयोजित प्रतिष्ठित शतरंज प्रतियोगिता जीतकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि के बाद तमिलनाडु सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और राज्य की ओर से 50 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। सोमवार को आयोजित एक विशेष समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रज्ञानानंदा को सम्मानित किया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिह्न भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, खेल विभाग के प्रतिनिधि और प्रज्ञानानंदा के माता-पिता भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि प्रज्ञानानंदा ने ओस्लो में आयोजित नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। शतरंज जगत में इस प्रतियोगिता को दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित स्पर्धाओं में गिना जाता है, जहां विश्व के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार प्रज्ञानानंदा का यह सफर आसान नहीं रहा है। प्रतियोगिता के शुरुआती छह दौर के बाद वह अंक तालिका में छठे और रैंकिंग भी गिरकर 16वें स्थान तक पहुंच गई थी। ऐसे में कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वह खिताब की दौड़ में वापसी कर पाएंगे। हालांकि युवा भारतीय खिलाड़ी ने शानदार संघर्ष का परिचय दिया और लगातार चार मुकाबले जीतकर पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदल दी है। इस दौरान उन्होंने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दो बार हराकर सभी को चौंका दिया। इसके अलावा मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश के खिलाफ मिली जीत भी उनके अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

अंतिम स्थान पर थे। इसी दौरान उनकी विश्व

## ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा शतक

भारत ए के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई नेशन ए सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार शतक जड़ दिया। शुरुआती झटकों के बाद गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने भारतीय पारी को संभालते हुए बड़ी साझेदारी की। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेले जा रहे ट्राई नेशन ए सीरीज के पहले मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ दिया है। उन्होंने 112 गेंदों का सामना करने के बाद यह कारनामा किया। इस दौरान गायकवाड़ ने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दोनों सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह सिर्फ 16 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। वैभव सूर्यवंशी सस्ते में आउट हुए, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला और 140 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ दिया। आपको बता दें कि जब ट्राई नेशन ए सीरीज के लिए टीम चुनी गई थी, तब ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं चुना गया था। हालांकि रियान पराग के बाहर होने के बाद उन्हें मौका मिला और उन्होंने शतक लगाकर इस फैसले को सही साबित कर दिया। इस मुकाबले में वह 114 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी ओर तिलक वर्मा ने भी धीमी शुरुआत के बाद लय हासिल की और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि वह भी 60 रन बनाकर आउट हो गए।

## बोर्ड ने बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार जीत के बावजूद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की कप्तानी जा सकती है। दरअसल, मुकाबले में जीत के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन नाइटक्लब में गए, जिससे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया। बोर्ड ने बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के बाद टीम पर कर्फ्यू लगा दिया है। मतलब सीरीज के दौरान रात को कोई भी खिलाड़ी नाइटक्लब में नहीं जाएगा और ना ही शराब का सेवन करेगा। इसके बावजूद बेन स्टोक्स गस एटकिंसन के साथ नाइटक्लब पहुंच गए। सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क पर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद 8 जून की शाम को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि दोनों के खिलाफ प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच की जा रही है। दोनों दूसरे टेस्ट से बाहर रह सकते हैं, जो 17 जून से ओवल में खेला जाएगा। हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अब तक यह नहीं बताया कि नाइटक्लब में ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के खिलाफ जांच की जा रही है। आपको बता दें कि नॉटिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हरा दिया था। दूसरी पारी में एटकिंसन ने 5 विकेट हासिल किए थे और जीत में अहम भूमिका निभाई थी। जीत के बाद स्टोक्स ने कहा था कि उनकी खुशी तब तक अधूरी रहती है, जब तक वह खिलाड़ियों के साथ बीयर नहीं पी लेते। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि स्टोक्स या एटकिंसन को नाइटक्लब में कोई चोट नहीं आई है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वहां उनकी मारपीट हुई हो, क्योंकि उस समय रग्बी क्लब के खिलाड़ी भी वहां मौजूद थे, जो सीजन के अंत का जश्न मना रहे थे। एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि सरासेंस रग्बी क्लब के एक अकादमी खिलाड़ी ने कथित

तौर पर एटकिंसन पर घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन ECB सुरक्षा गार्ड पर लग गया। गार्ड को स्टिचेस लगे। हालांकि स्टोक्स और एटकिंसन ने आपा नहीं खोया और सुरक्षित रहे, लेकिन यह घटना टीम डिसिप्लिन पर सवाल खड़ा कर रही है। अब देखना ये होगा कि ECB की जांच में क्या निकलकर आता है।

# 'बंटवारा 1947' का फर्स्ट लुक जारी

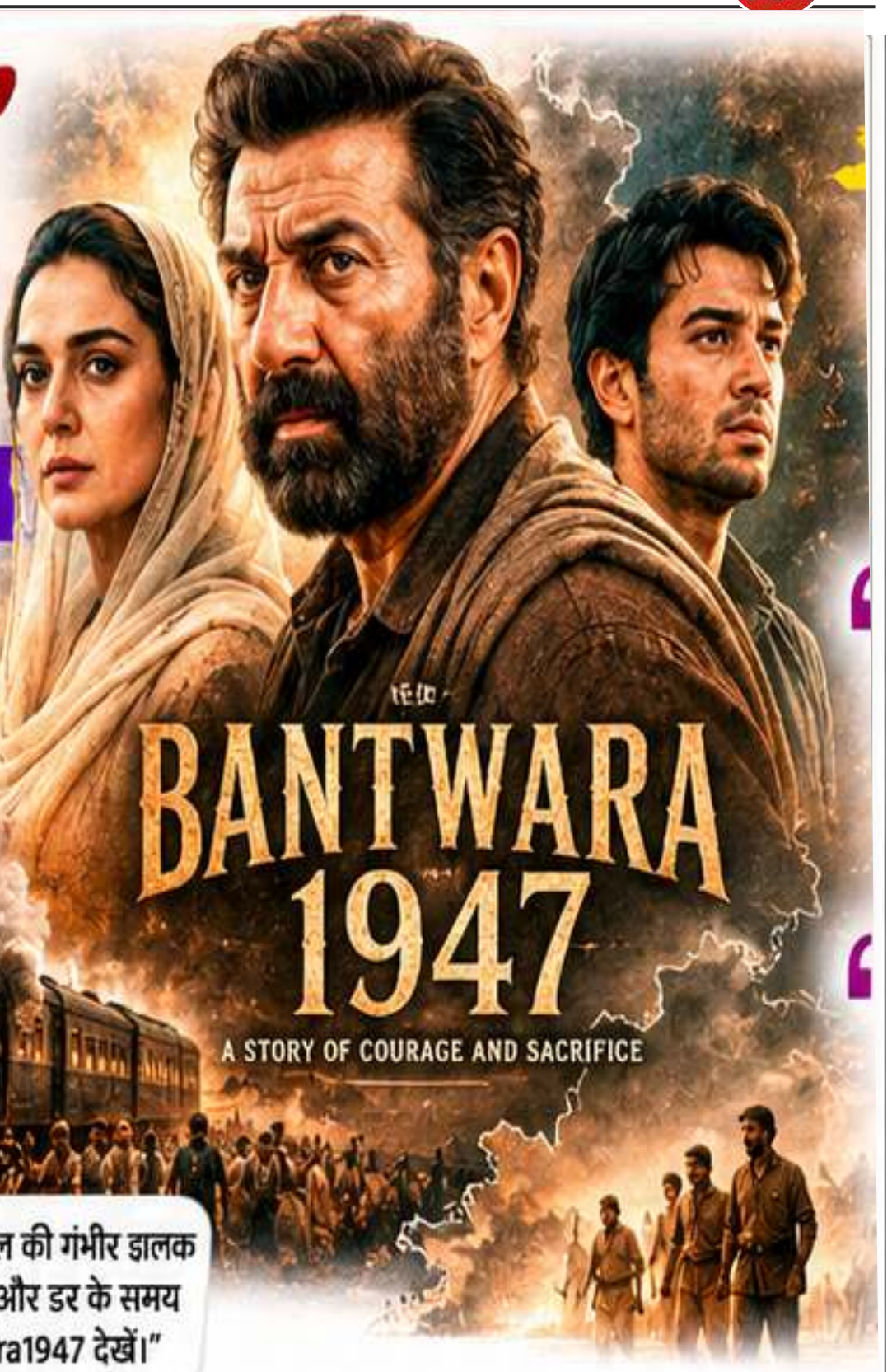


## 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

सनी देओल, प्रीति जिंटा और करण देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' का पहला आधिकारिक मोशन पोस्टर और फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया हैं। आमिर खान प्रोडक्शंज के बैनर तले बन रही यह फिल्म 14 अगस्त 2026, स्वतंत्रता दिवस के खास बीकेंड पर रिलीज होगी।

- पहले नाम था 'लाहौर 1947', अब बदलकर हुआ 'बंटवारा 1947'
- बॉक्स ऑफिस पर होगा मुकाबला इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' से

फर्स्ट लुक में सनी देओल का दमदार अवतार, प्रीति जिंटा और करण देओल की गंभीर झलक ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया हैं। पोस्ट के कैपशन में लिखा गया, "नफरत और डर के समय में, उन्होंने साहस को चुना। 14 अगस्त 2026 से सिनेमाघरों में #Batwara1947 देखें।"

# सोनम कपूर आज मना रही हैं 41वां जन्मदिन

## कभी एक्ट्रेस नहीं, डायरेक्टर बनना चाहती थीं

बॉलीवुड की फैशन आइकॉन सोनम कपूर आज 9 जून को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। कम लोग जानते हैं कि वह कभी एक्ट्रेम नहीं बल्कि डायरेक्टर बनना चाहती थीं।

### फिल्म निर्देशन में थी दिलचस्पी

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'ब्लैक' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। भंसाली ने उनकी प्रतिभा पहचानकर उन्हें एक्टिंग में आने की सलाह दी।

### बॉलीवुड डेब्यू

करीब डेढ़ साल तक मनाने के बाद सोनम ने 2007 में फिल्म 'सांवरिया' से बॉलीवुड में कदम रखा।

### पर्सनल लाइफ

साल 2018 में सोनम कपूर ने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की।

# ईशा देओल ने ex हस्बैंड भरत तख्तानी पर तोड़ी चुप्पी

## "हम अच्छी टीम की तरह निभा रहे हैं पेरेंटिंग"

सेपरेशन के बाद भी ईशा देओल और भरत तख्तानी अपनी बेटियों राध्या और मिराया की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं। ईशा ने कहा, "मैं खुद को अकेली मां नहीं मानती, हम दोनों अपमे बच्चों की खुशियों और बेहतर भविष्य के लिए एक टीम हैं।'

- माता-पिता का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, बच्चों के लिए प्यार और जिम्मेदारी हमेशा बरकरार।
- मां बनने के बाद प्राथमिकताएं बदलीं, बच्चों को समय देना सबसे जरूरी।
- 2012 में हुई थी शादी, दो बेटियों राध्या और मिराया की हैं माता।
- करियर के साथ अब परिवार को देती हैं सबसे ज्यादा महत्व।

# लखनऊ में नकली नोटों का बड़ा खेल बेनकाब

## तीन आरोपी गिरफ्तार

**मड़ियांव पुलिस ने 13.95 लाख रुपये की जाली करेंसी के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी आजमगढ़ से नकली नोट लेकर विभिन्न क्षेत्रों में खपाते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और बरामद नोटों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।**

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली करेंसी बदलने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 13.95 लाख रुपए के 500 और 100 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। डीसीपी नार्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया सोमवार को पुलिस प्रधान मैरिज लॉन चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि घैला पुल के पहले दाहिनी ओर खाली मैदान में बने टीन शेड के पास 3 युवक नकली नोटों के साथ किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपितों ने अपनी पहचान आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन निवासी आलोक सिंह (21), मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुबारक पट्टी वनकट निवासी सोनू गोंड उर्फ गोलू (25) और सिधारी थाना क्षेत्र के सारगढ़ निवासी वृजेश विश्वकर्मा (35) के रूप में बताई। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 500 रुपए के 1402 और 100 रुपए के 6946 जाली नोट बरामद हुए। कुल 13 लाख 95 हजार 600 नकली करेंसी बरामद हुई। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी आलोक सिंह और ब्रजेश बैंक में लोन दिलवाने का काम करते थे। सोनू चाय की दुकान चलाता था। पूछताछ में सामने आया तीनों आजमगढ़ के रहने वाले मंजीत नाम के व्यक्ति से नकली नोट लेते थे। जिसे अलग-अलग जगह पर खपाते थे। एक लाख के बदले 3 लाख नकली करेंसी देते थे। आरोपी लखनऊ में करेंसी किसको देने आए थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आरोपी अब तक कितनी नकली करेंसी बाजार में खपा चुके हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपियों के पास से बरामद नोटों के पेपर क्वालिटी में काफी अंतर है, हालांकि इसको कोई एक्सपर्ट ही पकड़ पाएगा। आम आदमी इसे असली नोट समझकर इस्तेमाल करता है। इसके ऊपर लगने वाली मैटेलिक पट्टी भी अलग से उभरी हुई दिखती है। पुलिस अब इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी।

## लखनऊ में भी सोमवार को तपिश और गर्मी ने लोगों को बेहाल किया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश में बढ़ती तपिश और गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सोमवार को प्रदेश के लगभग 25 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में हालात और भी खराब रहे। वाराणसी, चुर्क, बांदा,आगरा और प्रयागराज आदि जिलों में आसमान से जैसे आग बरसी। वहीं गोरखपुर, जालौन जैसे प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई समेत कुछ जिलों में दोपहर से पहले बादलों की आवाजाही दिखी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मौसम का यह उतार चढ़ाव जारी रहने वाला है। 09 और 10 जून को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में बढ़त आएगी। इसके बाद 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से 13 जून तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तेज हवाएं और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। सोमवार को 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ वाराणसी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा बांदा में 42.6 डिग्री, प्रयागराज में 42.5 डिग्री, चुर्क में 42.3 डिग्री और झांसी में 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। हालांकि, देर रात फिर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने वाला है। धूप की तल्खी और गर्म हवाओं से लू जैसी परिस्थितियां बनने के आसार हैं।

# मंत्री सुरेश खन्ना अपने सरकारी आवास से विधानसभा स्थित कार्यालय तक ई-रिक्शा से पहुंचे

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एक बार फिर ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए बड़ी पहल की है। मंत्री सुरेश खन्ना अपने सरकारी आवास से विधानसभा स्थित कार्यालय तक ई-रिक्शा से पहुंचे और प्रदेशवासियों से भी ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक परिवहन साधनों को अपनाने की अपील की। यह चौथा अवसर है जब उन्होंने कार्यालय आने-जाने के लिए ई-रिक्शा का उपयोग किया है। सुरेश खन्ना पहले भी ऊर्जा संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देते रहे हैं। इससे पूर्व वे एक बार साइकिल, एक बार मोटरसाइकिल तथा दो बार ई-रिक्शा का उपयोग कर कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि यह केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि समाज में ऊर्जा बचत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। वित्त मंत्री ने कुछ समय पहले यह संकल्प लिया था कि सप्ताह में कम से कम एक दिन वे पेट्रोलियम आधारित वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे अथवा न्यूनतम ईंधन खपत वाले साधनों से यात्रा करेंगे। इसी संकल्प के तहत उन्होंने एक बार फिर ई-रिक्शा से सफर कर लोगों को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी दैनिक जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करे तो इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव देश की ऊर्जा जरूरतों और पर्यावरण पर पड़ सकता है। सुरेश खन्ना ने कहा कि विश्व स्तर पर बदलती परिस्थितियां और खाड़ी क्षेत्र में जारी अस्थिरता ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को और बढ़ा रही हैं। भारत जैसे बड़े देश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और कीमतें अंतरराष्ट्रीय हालात से प्रभावित होती हैं। ऐसे में ऊर्जा की बचत और वैकल्पिक साधनों का उपयोग समय की मांग है। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक अनावश्यक वाहन उपयोग को कम करें और सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या ई-रिक्शा जैसे साधनों को अपनाएं तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

## अखिलेश यादव ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' का कद घटने पर कसा तंज

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' का कद घटने पर तंज कसा। उन्होंने मंगलवार को X पर लिखा- अभी हाफ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे। जब सारे घटिया एक्सप्रेस-वे बन गए और भ्रष्टाचार का आपसी लेनदेन का टारगेट पूरा हो गया, तब हटाया तो क्या हटाया? इससे पहले, सोमवार को यूपी सरकार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्री नंदी से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की जिम्मेदारी वापस ले ली थी। अब एक्सप्रेस-वे के निर्माण और विकास से जुड़ी सभी जिम्मेदारी सीधे सीएम योगी संभालेंगे। इसके लिए यूपीडा को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास विभाग से जोड़ दिया गया है। अभी तक यूपीडा से जुड़ी परियोजनाओं, बजट और मंजूरी से संबंधित फाइलें औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' के जरिए आगे बढ़ती थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये फाइलें सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस से क्लियर की जाएंगी। अखिलेश ने लिखा- सुना है इलाहाबाद की सारी सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये सारे विधायक और प्रत्याशी केवल खाने-कमाने में लगे रहे और लोकसभा सीट हाथ से निकल गई। यही फॉर्मूला यूपी की उन सभी 43 लोकसभा सीटों पर लागू किया जा रहा है, जहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी। बाकी उन 9-10 सीटों पर भी जहां भाजपा हेरफेर करके सर्टिफिकेट से जीती थी, वोट से नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। वैसे तो सुना है कि भाजपा के वर्तमान विधायक खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि 'पीडीए' के सामने उनके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के मूल वोटर अब एक-चौथाई भी नहीं रह गए हैं।

## मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इंडिया गठबंधन परमुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगाया

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जो लोग सांप्रदायिकता खत्म करने की बात करते हैं, उन्होंने अपने एजेंडा और बातचीत में 'सांप्रदायिक' जैसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। आज के माहौल में भाईचारे और एकजुटता की बहुत जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और विशेषकर राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से सावधान रहने की सलाह दी। शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन में मुस्लिम समुदाय की अनदेखी की गई। बैठक में किसी भी प्रमुख मुस्लिम पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। उन्होंने गठबंधन के नेताओं पर आरोप लगाया कि वे सांप्रदायिकता खत्म करने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने संवाद में इस शब्द का प्रयोग भी नहीं करते। बरेलवी ने देश में भाईचारे और एकजुटता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। मौलाना रजवी ने कहा कि अखिलेश यादव ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खड़े किए थे। उनके इस कदम से कांग्रेस को नुकसान हुआ और इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी।

# 12.20 लाख से अधिक पांडुलिपियां डिजिटल रूप में संरक्षित की गईं

भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ज्ञान भारतम् मिशन के तहत प्रदेश के 71 जिलों से अब तक 12 लाख 20 हजार 432 से अधिक दुर्लभ और ऐतिहासिक पांडुलिपियों का विवरण ज्ञान भारतम् पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से सदियों पुराने ज्ञान को सुरक्षित रखने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञान भारतम् मिशन के तहत चल रहे व्यापक सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण अभियान ने प्रदेश को पांडुलिपि संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, संस्कृति और इतिहास के अनमोल खजाने को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। ज्ञान भारतम् पोर्टल पर अपलोड की गई पांडुलिपियों के आंकड़ों के अनुसार वाराणसी प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहां से कुल 3 लाख 12 हजार 724 पांडुलिपियों का विवरण दर्ज किया गया है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध वाराणसी सदियों से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। यही कारण है कि यहां बड़ी संख्या में दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां संरक्षित रूप में उपलब्ध हैं। वाराणसी की पांडुलिपियों में वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र, कृषि विज्ञान और भगवान बुद्ध से संबंधित दुर्लभ साहित्य शामिल है। विशेष रूप से संस्कृत भाषा में लिखित ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद पदपाठ, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक भाष्य, रुद्री, शांति मंत्र, पवमान सूक्त तथा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित पांडुलिपियां भारतीय ज्ञान परंपरा की महानता को दर्शाती हैं। पांडुलिपियों के संरक्षण और सूचीकरण के मामले में अयोध्या और रामपुर भी अग्रणी जिलों में शामिल हैं। अयोध्या से 2 लाख 44 हजार 644 पांडुलिपियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जबकि रामपुर से 2 लाख 32 हजार 735 पांडुलिपियों की जानकारी अपलोड की गई है।

# पुरवा में 2000 बीघा अवैध कब्जे का दावा सपा पर भाजपा विधायक का बड़ा हमला

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के पुरवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक अनिल सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अवैध कब्जों, जुए और सट्टे के कारोबार को लेकर सपा को घेरा। विधायक ने दावा किया कि पुरवा विधानसभा क्षेत्र में करीब 2000 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसकी पूरी सूची जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत में विधायक अनिल सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी और अन्य जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही उन लोगों के नाम उजागर किए जाएंगे, जिन्होंने कथित तौर पर जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। भाजपा विधायक ने पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक और उनके करीबी लोगों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ लोगों के संरक्षण में सट्टा और जुआ जैसे अवैध कारोबार संचालित हो रहे हैं। विधायक ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में जुआ खिलवाने वालों और गलत गतिविधियों में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अनिल सिंह ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो स्थानीय पुलिस के साथ-साथ विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की मदद से भी कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके कृत्यों का जवाब देना होगा।विकास कार्यों को

लेकर भी विधायक अनिल सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने पूर्व विधायक को लगभग दो दशक तक अवसर दिया, लेकिन क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो सका। इसके विपरीत, भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों ने सड़क, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने, सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण तथा जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया गया है। विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र का समग्र विकास और जनता की सेवा है।समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए अनिल सिंह ने कहा कि "खाली प्लॉट हमारा है" अब सपा की पहचान बन चुकी है। उन्होंने जनता से अपील की कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाहों से सावधान रहें तथा विकास के मुद्दों पर ध्यान दें।

## तेज आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जिले में देर रात करीब सवा दो बजे आई तेज आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नीम का पेड़ गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। दो बकरियां और एक मवेशी की भी मौत हो गई। माखी थाना क्षेत्र के मेथीटीकुर के मजरा दोस्तअली खेड़ा निवासी किसान झूरी (71) नीम के पेड़ के नीचे झोपड़ी में तख्त पर सो रहे थे। देर रात तूफान से पेड़ पलट गया और उनकी मौत दबकर हो गई। परिजनों ने तख्त को तोड़कर निकाला। पुलिस और लेखपाल को सूचना दी। चकलवंशी चौराहे पर बिजली का खम्भा टूटने से जाम लग गया। चारों मार्गों पर पेड़ बिजली के खम्भे गिरने से आवागमन बंद हो गया। सफीपुर में बडादेव के पास रेल मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। कानपुर से बालामऊ जाने वाली ट्रेन खड़ी हो गई। सफीपुर में पुलिस परीक्षा केंद्र के सामने नीम का पेड़ गिर गया। इसके अलावा करीब डेढ़ सौ पोल टूटने से शहर से लेकर गांव तक की बिजली गुल हो गई। एडीएम सुशील कुमार गोंड ने बताया कि तूफान से हुए नुकसान का आंकलन कराया जा रहा है।

## लिखित परीक्षा का दूसरा दिन मंगलवार को भी कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न

उन्नाव में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती (एनरोलमेंट-2025) लिखित परीक्षा का दूसरा दिन मंगलवार को भी कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रहा है। जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर 3662 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है।परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को गहन तलाशी, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। मंगलवार सुबह से ही विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखी गईं। आगरा, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अभ्यर्थी परीक्षा देने उन्नाव पहुंचे हैं। केंद्रों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जहां अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और पहचान पत्रों की गहन जांच की जा रही है। जिले में अटल बिहारी इंटर कॉलेज, डीएसएन इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ओपीडी इंटर कॉलेज, श्यामलाल इंटर कॉलेज, एसएवी इंटर कॉलेज और अचलगंज सहित कुल 12 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रशासन के अनुसार, लगभग 3662 अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही परीक्षा कक्षों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा की निगरानी के लिए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी न हो। इसके लिए शहर में पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां बाहर से आए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों की जानकारी और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

## उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से यह ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें व्यापारियों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजा जा रहा है। रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि यह ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य वर्गों के लिए कई बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जीएसटी पंजीकृत व्यापारी अभी भी ऐसी सुविधाओं से वंचित हैं। व्यापार मंडल ने सभी जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग की, ताकि बीमारी या आकस्मिक स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। दूसरी प्रमुख मांग के रूप में, व्यापार मंडल ने जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की दुकानों के लिए एक करोड़ रुपये तक के अग्नि एवं दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करने को कहा। उनका तर्क था कि आगजनी जैसी घटनाओं से व्यापारियों को भारी नुकसान होता है, इसलिए सरकार को इस संबंध में एक विशेष योजना लागू करनी चाहिए। ज्ञापन में जीएसटी और आयकर विभागों द्वारा विलंब से कर जमा करने पर लगाए जाने वाले 18 प्रतिशत ब्याज को कम करने की भी मांग की गई। श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार जहां जमा धनराशि पर कम ब्याज देती है, वहीं व्यापारियों से 18 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूला जाता है। इसे घटाकर 9 प्रतिशत करने का आग्रह किया गया है। व्यापारियों ने विभिन्न विभागों में लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन विभागों में आजीवन लाइसेंस की व्यवस्था लागू हो चुकी है, उसी तर्ज पर अन्य विभागों में भी लाइसेंस को आजीवन मान्यता दी जाए। इससे व्यापारियों को बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ज्ञापन में विभागीय सर्वे, छापेमारी और सैंपलिंग के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग शामिल है। व्यापार मंडल का कहना है कि आयकर, जीएसटी और अन्य विभागों के अधिकारी बिना स्पष्ट पहचान के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पहुंचते हैं, जिससे भ्रम और उत्पीड़न की स्थिति पैदा होती है।

## संत की चाकू से गोद कर हत्या, घटनास्थल पर जांच

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जिले में बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के घूरे टोला मोहल्ले में निर्माणाधीन मंदिर की रखवाली कर रहे संत की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की और जल्द खुलासे की बात कही है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के घूरेटोला मोहल्ला निवासी संत मिलनदास (60) पहले बाबा बोधेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके बाद में अपना खुद का मंदिर बनवा रहे थे। बड़े भाई वीरेंद्र ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वह खाना खाने के बाद मंदिर निर्माण की देखरेख करने के लिए गए थे। घर से करीब 200 मीटर मंदिर होने से वहीं अज्ञात लोगों ने उनके पीठ पर चाकू से दो वार कर घायल कर दिया। वहां से गुजर रहे सभासद अतीक ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हत्या की सूचना पर पुलिस और बाद में विधायक श्रीकांत कटियार भी पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से घटना की जल्द खुलासे की बात कही है। उन्होंने शादी नहीं की थी। वह छह भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। कोतवाल अखिलेशचंद्र पांडेय ने बताया कि चाकू से वार कर हत्या की गई है। परिजनों ने किसी पर अभी कोई शक नहीं जताया है। जांच की जा रही है।

## सड़क हादसे में निजी अस्पताल की नर्स की मौत

लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र स्थित जॉगर्स चौराहे पर मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में निजी अस्पताल की नर्स की मौत हो गई। ड्यूटी से घर लौट रही नर्स को सड़क पार करते समय मौरंग लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। ट्रॉली पलटने से वह उसके नीचे दब गईं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। जानकारी के अनुसार, उन्नाव के पनापुर कलां लगलेसरा निवासी साधना (26) पुत्री राम विशुन दुबग्गा क्षेत्र के विकल्प अस्पताल में नर्स थीं। मंगलवार सुबह शिफ्ट खत्म होने के बाद वह पैदल घर जा रही थीं। सुबह करीब 8:30 बजे जॉगर्स चौराहे पर सड़क पार करते समय मौरंग लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली (संख्या यूपी-32-एलपी-1910) ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुर्घटना के दौरान ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और साधना मौरंग के साथ उसके नीचे दब गईं। सूचना मिलने पर दुबग्गा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में विकल्प अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

# राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन के पुनर्गठन की तैयारी

## भाजपा में नियुक्तियों पर अंतिम मंथन

**राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि उत्तर प्रदेश को इस बार राष्ट्रीय संगठन में पहले से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल प्रदेश भाजपा के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उत्तर प्रदेश के नेताओं की भूमिका और प्रभाव को नई मजबूती**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन और उत्तर प्रदेश इकाई में जल्द ही बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम के गठन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों की मानें तो नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। पार्टी नेतृत्व प्रदेश के अनुभवी और सक्रिय नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, भाजपा की नई राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम में उत्तर प्रदेश से एक राज्यसभा सदस्य की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा एक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) को भी राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संगठन के भीतर इन नियुक्तियों को लेकर मंथन अंतिम चरण में बताया जा रहा है। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उत्सुकता बढ़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा अगले दो से चार दिनों के भीतर की जा सकती है। संगठन स्तर पर विभिन्न नामों पर विचार-विमर्श का दौर जारी है और क्षेत्रीय, सामाजिक तथा राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अंतिम सूची तैयार की जा रही है। पार्टी के अंदरूनी जानकारों का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में युवा नेताओं के साथ-साथ अनुभवी चेहरों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। भाजपा आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठन विस्तार की रणनीति को ध्यान में रखते हुए संतुलित टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश संगठन की नई टीम के गठन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में भी विस्तार और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्यों से सक्रिय और प्रभावशाली नेताओं को जिम्मेदारी सौंप सकता है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और भाजपा के लिए भी यह राज्य संगठनात्मक और चुनावी दृष्टि से बेहद अहम है। यही वजह है कि राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश के नेताओं का अनुभव और राजनीतिक पकड़ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान कर सकती है।

## एक प्राथमिक स्कूल में कथित तौर पर अश्लील डांस हुआ

यूपी के सरकारी स्कूलों के बाहर ही लिखा होता है कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। लेकिन जब इन स्कूलों का दुरुपयोग होने लगे तो क्या कहिएगा। ऐसा ही एक वाकया बलिया में सामने आया है। यहां के एक प्राथमिक स्कूल में कथित तौर पर अश्लील डांस हुआ। यूपी के स्कूलों में अभी गर्मी की छुट्टी चल रही हैं। इसी दौरान ये घटना सामने आई। जब इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जिम्मेदारों की आंखें खुली और कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलिया के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कथित तौर अश्लील डांस की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि यहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये सब हुआ। मामला इतना ही नहीं है, बताया तो ये भी जा रहा कि पूरा प्रोग्राम ही अवैध रूप से करवाया जा रहा था। अब जिस व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को करवाया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पता चला है कि बलिया के स्कूल में जो डांस हुआ, उसका वीडियो बना लिया गया था। जो सोमवार सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि ये यहां के सीयर ब्लॉक के तारणपुर गांव में स्कूल का है, जहां दो डांसर भी नजर आ रही हैं। इस मामले में जब बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल तो 20 मई से 20 जून तक गर्मी के छुट्टी के लिए बंद हैं। बलिया के बीएसए से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश प्रसाद इस वक्त जनगणना के कार्य में व्यस्त हैं। वे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बीएसए सिंह का कहना है कि तारणपुर के राम बच्चू भारती की बेटी की 29 मई 2026 को शादी हुई थी। राम बच्चू भारती ने अवैध रूप से स्कूल परिसर में बारात रुकने की व्यवस्था की थी। इसी दौरान गीत और नृत्य प्रस्तुत करने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया था।

## परीक्षा देने जा रही दो युवतियों के साथ ऑटो चालक ने जबरदस्ती करने की कोशिश की

लखनऊ में परीक्षा देने निकली दो युवतियों के साथ दरिंदगी की कोशिश करने वाले ऑटो चालक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पहले दोनों युवतियों को चारबाग बस अड्डे से ऑटो में बैठाया और फिर उन्हें सुनसान इलाके में ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने मारपीट की और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान हसीब के रूप में हुई है, जो हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र के मिर्जानिपुर गांव का रहने वाला है। फिलहाल वह लखनऊ के पारा इलाके में रह रहा था। बताया जा रहा है कि 7 जून यानी रविवार सुबह दोनों युवतियां परीक्षा देने जा रही थीं। इसी दौरान चारबाग बस अड्डे के पास आरोपी ने उन्हें आलमबाग छोड़ने के बहाने अपने ऑटो में बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में वह ऑटो को पारा थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड के पास सुनीसान जगह पर ले गया और वहां दोनों युवतियों के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब युवतियों ने विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। किसी तरह पीड़िता पुलिस तक पहुंची और घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी के ऑटो को घेरने की कोशिश की, लेकिन खुद को फंसता देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया ऑटो, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि हसीब पहले भी इसी तरह के मामलों में शामिल रह चुका है। साल 2024 में हरदोई के संडीला इलाके में उसने एक महिला को ऑटो में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया था।

## स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी करणी सेना,भाजपा पर तंज, बिरादरी का समर्थन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (U P Assembly Elections) की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा, कांग्रेस और बसपा के बाद अब नए राजनीतिक दल की एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने विधानसभा चुनाव में करणी सेना ने 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। करणी सेना ने उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने शाहजहांपुर में प्रदेश कार्य समिति बैठक के दौरान यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, लेकिन हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। अम्मू ने आगे कहा कि हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने यूपी में स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। अम्मू ने कहा कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। हम लगातार अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। इस ऐलान के साथ ही करणी सेना प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। करणी सेना प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आप राजभर जैसे लोगों को मंत्री बना सकते हैं और अपना दल, सुहेलदेव समाज पार्टी जैसी छोटी पार्टियों को सीटें दे सकते हैं तो हम क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते? उन्होंने कहा कि हमारे साथ सभी बिरादरियों के लोग जुड़े हैं। सूरजपाल सिंह अम्मू ने भाजपा की क्षेत्रीय दलों को तरजीह देने की नीति पर भी ऐतराज जताया। सूरजपाल सिंह अम्मू ने शाहजहांपुर दौरे के समय दो प्रमुख मांगों पर जोर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की मांग की। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात में UCC लागू हो चुका है। अब यूपी में भी इसे लागू किया जाए।